व्यवस्था-परिवर्तन
एक विमर्श

व्यवस्था-परिवर्तन
एक विमर्श

पहल एक 'नए भारत' के रचना की

मनोहर मनोज

Economy India
Publications

Published by

Add: 303, Himgiri Tower, Kaushambi, Ghaziabad-201010
Phone: 0120-4314716
E-mail: economyindia@gmail.com

First Edition 2019
Copyright © Manohar Manoj, 2019
ISBN : 978-81-939336-4-0

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. Application for such permission should be addressed to the publisher.

Disclaimer

The author and the publisher have taken every effort to the maximum of their skill, expertise and knowledge to provide correct material in the book. Even then if some mistakes persist in the content of the book, the publisher does not take responsibility for the same. The publisher shall have no liability to any person or entity with respect to any loss or damage caused, or alleged to have been caused directly or indirectly, by the information contained in this book.

The publisher has fully tried to follow the copyright law. However, if any work is found to be similar, it is unintentional and the same should not be used as defamatory or to file legal suit against the authors/publisher.

If the readers find any mistake we shall be grateful to them to point those to us so that these can be corrected in the next edition.

All disputes are subject to the jurisdiction of Delhi court only.

Printed in India at Milan Enterprises, Daryaganj, New Delhi-110 002

यह पुस्तक सिस्टम, समाज, सरकार तथा सभी तरह के सार्वजनिक संस्थाओं के समूचे क्रियाकलापों की बेहतरी के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है तथा देश में सभी तरह के यथोचित बदलावों तथा भ्रष्टाचार की बेहद दुरूह समस्या के समाधान के लिए मनसा वाचा कर्मणा संलग्न है।

इस पुस्तक में दर्ज सभी सार्वजनिक आँकड़े, तथ्य व घटनाएँ 31 जुलाई, 2018 तक अद्यतन हैं।

नए परिवर्तन की पहल क्या होनी चाहिए ?

हमारी नजर में यह न तो साम्यवाद होना चाहिए, न पूँजीवाद और न ही समाजवाद,
यह तो सिर्फ सुधारवाद होना चाहिए।

नया परिवर्तन कोई ढकोसलावाद नहीं होना चाहिए,
यह सिर्फ पारदर्शितावाद होना चाहिए।

हमें नहीं जरूरत है—जुमलों की, हमें जरूरत है—मुद्दों को
तलाशने की और उसके ईमानदार समाधान की।

हमें नहीं जरूरत है, नकारात्मकतावाद की,
हमें जरूरत है—नवप्रवर्तनवाद की।

हमें नहीं जरूरत है—थोथे नारों की,
हमें जरूरत है वैचारिक परिवर्तन लाने की।

हमें नहीं जरूरत है—गुमराह करनेवालों की,
हमें जरूरत है—सही राह दिखाने वालों की।

हमें नहीं जरूरत है यथास्थितिवाद की,
हमें जरूरत है—गुड गवर्नेंस की, गुड पॉलिटिक्स की,
गुड सोसाइटी की और गुड कल्चर की।

हमें नहीं जरूरत है—पहचान, यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की,
हमें जरूरत है—क्वालिटी लीडरशिप की।

हमें नहीं जरूरत है—आंदोलन की,
हमें जरूरत है—पब्लिक लीडरशिप की
पाठशाला विकसित करने की।

हमें नहीं जरूरत है—भ्रष्टाचार पर केवल आरोप लगाने वालों की,
हमें जरूरत है—भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार करनेवालों की।

हमें नहीं जरूरत है—तुष्टीकरण की,

हमें जरूरत है सच्चे व सैद्धांतिक सेकुलरिज्म की।
हमें नहीं जरूरत है—पापुलिस्ट इकोनॉमी की,
हमें तो जरूरत है सस्टेनेबल इकोनॉमी की।
हमें नहीं जरूरत है—सब्सिडी की, हमें जरूरत है—सपोर्ट की।
हमें नहीं जरूरत है—नियंत्रण की,
हमें जरूरत है—प्रतियोगिता मूलक बाजार की।
हमें नहीं जरूरत है—सामाजिक न्याय की, हमें जरूरत है—
सर्वांगीण सामाजिक न्याय और विराट् संवेदनशीलता की।
हमें नहीं जरूरत है—आरक्षण की, हमें जरूरत है—सशक्तीकरण की।
हमें नहीं जरूरत है—स्वतंत्र मीडिया की, हमें जरूरत है
सशक्त, संवैधानिक और समतामूलक मीडिया की।
हमें नहीं जरूरत है—ब्यूरोक्रेसी (नौकरशाही) की,
हमें जरूरत है—रेगुलेटरी अथोरिटी (नियमन प्राधिकरण) की।
हमें नहीं जरूरत है—शासक और शासित संबंधों की,
हमें जरूरत है—प्रबंधक और ग्राहक सरीखे संबंधों की।
हमें नहीं जरूरत है—मोनोपोली (एकाधिकार) की,
हमें जरूरत है—कम्पीटिशन (प्रतियोगिता) की।
हमें नहीं जरूरत है—करवंचकों की, हमें जरूरत है—कर सुधारों की।
हमें नहीं जरूरत है—कृषि को कृषकाय बनाने की,
हमें जरूरत है—कृषि को लाभदेय बनाने की।
हमें नहीं जरूरत है—संविधान की परिक्रमा लगाने की,
हमें जरूरत है—देश काल और परिस्थिति के मुताबिक
उसमें समुचित संशोधन लाने की।
हमें जरूरत है—लोकतंत्र के चारों खंबों और तीनों टायर को
नए सिरे से परिभाषित करने की।
हमें नहीं जरूरत है—कार्यपालिका को सर्वेसर्वा बनाने की,
हमें जरूरत है—विधायिका को वास्तविक रूप से मजबूत व सर्वोच्च बनाने की।
और अंत में हमें जरूरत नहीं है उपरोक्त सभी कार्यों व संकल्पों को
फकत भावभूमि पर उतारने की, बल्कि हमें जरूरत है इन्हें कार्यभूमि,
अर्थभूमि और बदलाव भूमि पर अमल में लाने की।

दो शब्द

यह पुस्तक भारत के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण और व्यापक निर्माण के लिए है, जिसमें भाषिक बाजीगरी और भावुकता से भरे जुमलों का प्रस्तुतीकरण नहीं है बल्कि अनेकानेक ठोस एजेंडों और देश के तमाम क्षेत्रों में मूलभूत सुधारों का एक संपूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से खींचा गया खाका है। इस पुस्तक में देश की मौजूदा विभिन्न व्यवस्थाओं में व्याप्त खामियों, अवरोधों और जरूरतों को हू-ब-हू दरशाते हुए उसके निराकरण के लिए बिल्कुल सटीक सुझावों और उपायों, जिसमें कहीं संवैधानिक बदलाव शामिल है, कहीं कानूनी बदलाव शामिल है, कहीं नीतिगत बदलाव शामिल है, कहीं संस्थागत बदलाव शामिल है, कहीं क्रियान्वयनगत बदलाव शामिल है, कहीं गवर्नेंस तकनीकों के प्रचलन का विस्तार शामिल है, कहीं संचार व डिलीवरी मैकेनिज्म को त्वरित, दोषमुक्त और शिकायतरहित बनाने की बात शामिल है।

कुल मिलाकर यह पुस्तक व्यवस्था परिवर्तन के मूल तत्त्वों के बदलाव और आवश्यक प्राथमिकताओं के बेहतर निर्धारण की बात करती है, जिससे कि इससे जुड़े चौतरफे बदलावों का मार्ग स्वयंमेव प्रशस्त हो और भ्रष्टाचार जैसी विकराल और बेहद दुरूह समस्या का संपूर्ण समाधान हासिल हो। पूरी व्यवस्था का प्राथमिक तौर पर व्याकरण गढ़ने का कार्य इस पुस्तक में शामिल है। हमने इस पुस्तक में देश की तमाम व्यवस्था की छान-बीन के दौरान चार तरह की स्थितियाँ पाई हैं। पहली कुछ चीजें अच्छी हैं, दूसरी कुछ चीजें और अच्छी स्थिति में हैं, तीसरी कुछ चीजें खराब हैं तो चौथी कुछ चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं। इन चारों स्थितियों में से अंतिम तीनों स्थितियों को पहली स्थिति में लाने हेतु मिशन गढ़ने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। इस पहली स्थिति से जुड़े कई प्रेरक बिंदु और रोल मॉडल हमारे देश में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर देश में पोलियो उन्मूलन का एक जीवंत, सतत और समावेशी अभियान चलाया गया। देश में मोबाइल क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसे जन-जन के विकास व संचार के सशक्तीकरण को अंजाम देने में सफलता हासिल हुई है। तीसरा, देश में सूचना प्रौद्यागिकी के विस्तार के कारवाँ का लगातार बढ़ना भी शामिल है।

इन तीनों प्रेरक बिंदुओं के अलावा हमारे पास कई अलग-अलग सेक्टर में सफलता की इबारत के नायाब नूमने मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में सहकारिता की संस्थागत तकनीक के जरिए श्वेत क्रांति का आगमन हुआ। सार्वजनिक परिवहन के इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में डी.एम.आर.सी. की स्थापना व विस्तार मौजूद है। शहरी संपत्ति परिसीमन कानून को हटाकर देश के रियल इस्टेट उद्योग के तीव्र विकास का मॉडल मौजूद है। प्रशासन के क्षेत्र में नियमन प्राधिकरण की बेहतर मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इन सभी प्रेरक बिंदुओं को लेते हुए हमारे सामने मूलभूत और सेक्टरगत सुधारों के तमाम एजेंडों को दरशाने का कार्य इस पुस्तक में किया गया है।

यह पुस्तक देश की सारी समस्याओं की जननी भ्रष्टाचार का एक पक्षीय नहीं, बल्कि संपूर्ण पक्षीय समाधान प्रस्तुत करती है। कुल मिलाकर यह पुस्तकीय विचारपुंज इस देश की भावभूमि पर पड़े बेकार के बतंगड़ विचारों में उलझने के बजाय, इसकी अर्थ भूमि पर मौजूद अनेकानेक सुधारों के फार्मूले, जिसमें संविधानगत, कानूनगत, नीतिगत, संस्थागत, तकनीकीगत, परिवेशगत एवं विचारगत बदलावों के जरिए देश की सभी प्रमुख समस्याओं के ठोस व स्थायी समाधान करने का प्रयास प्रस्तुत करती है।

यह पुस्तक दो भागों में बाँटी गई है। पहला भाग है सुधारों का वस्तुनिष्ठ एजेंडा और इसका निराकरण मॉडल। दूसरा भाग है इन सभी सुधारों का सेक्टरवार विषयगत विश्लेषण।

1. वस्तुनिष्ठ खंड : पुस्तक के इस हिस्से में, हमने देश के करीब छह मौलिक क्षेत्रों, मसलन (1) देश का जातीय व राष्ट्रीय एजेंडा व इसकी सुधार योजना; (2) देश का राजनीतिक एजेंडा और उसकी सुधार योजना; (3) देश की आर्थिक व्यवस्था और इसकी सुधार योजना; (4) देश के प्रशासनिक सुधार का एजेंडा और इसकी सुधार योजना; (5) देश के सामाजिक सुधार का एजेंडा और इसकी सुधार योजना, और (6) विभिन्न संस्थाओं के सुधार का एजेंडा और की बातें प्रस्तुत की हैं।

साथ ही क्षेत्रवार सुधार एजेंडों के अलावा देश की त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विभिन्न मंत्रालयीय व विभागीय सुधार एजेंडे को वस्तुनिष्ठ व त्वरित उपायों के तरीके से प्रस्तुत किया है। करीब 25 मंत्रालयों के सुधार एजेंडे, जिनमें संवैधानिक बदलावों से लेकर कानूनी, नीतिगत, संस्थागत, क्रियान्वयनगत, तकनीकीगत सुधारों की बातें शामिल हैं, इस पुस्तक में प्रस्तुत की हैं।

2. विषयगत खंड : पुस्तक के इस हिस्से में हमने उपरोक्त सभी वस्तुनिष्ठ एजेंडों और उनके समाधान की विस्तृत विषयपरक प्रस्तुति की है। इसके तहत हमने देश के तमाम मुद्दों, समस्याओं, सवालों और मूल व्यवस्था में परिवर्तन लाने के विचारगत समाधान वाले करीब 60 कार्योत्तेजक और विचारोत्तेजक आलेख शामिल किए हैं।

ये सभी लेख देश में पिछले एक दशक के दौरान यूपीए-1 एवं 2 तथा एनडीए-2 के शासनकाल में उपस्थित राजनीतिक-आर्थिक प्रशासनिक परिस्थितियों, घटनाओं, मुद्दों, निर्णयों तथा जनांदोलनों एवं विभिन्न राजनीतिक-सामाजिक गतिशीलताओं के बरअक्स उपजे सवालों पर आधारित हैं। यह सभी लेख देश में पिछले दस साल में घटित समकालीन त्वरित मुद्दों से उपजे हैं, परंतु उनके सरोकारों को देश की राष्ट्रीय-जातीय, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं अनेकानेक संस्थाओं की दीर्घकालीन पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर रेखांकित किया गया है। कुल मिलाकर यह पुस्तक हमारी समूची व्यवस्था की विडंबना एवं व्यवस्था की बेहतरी के बीच संतुलन की तलाश करती है। आशा है देश की व्यवस्था के तमाम सरोकारों में दिलचस्पी रखनेवाले पाठक इस पुस्तक के पठन-मनन के जरिए हमारे प्रयासों को साधुवाद देने की कृपा करेंगे। अंत में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह पुस्तक केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि यह देश, समाज और पूरी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए वैचारिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक जागरण लाने का एक ऐसा अभियान है जो निरंतर रचनात्मक और सकारात्मक रूप से चलायमान है।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक के लेखन के दौरान इसमें वर्णित परिवर्तन और सुधार के अधिकतर एजेंडे सरकारों द्वारा लागू नहीं किए गए थे। परंतु अब इस पुस्तक के प्रकाशन के समय इनमें से कुछ एजेंडों पर मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जरूर पहल दरशाई गई है। पर अभी भी इस पुस्तक में वर्णित अनेकानेक एजेंडों पर काम होना बाकी है।

—मनोहर मनोज

अनुक्रम

दो शब्द *9*

भाग–1 (वस्तुनिष्ठ खंड)
मौलिक सुधार एजेंडों का वस्तुनिष्ठ खंड

1. भारत में सुधारों का एजेंडा **21**
- क्षेत्रवार सुधार योजना 21
- भारत की राष्ट्रीय व जातीय स्थिति और इसकी सुधार योजना 22
- राजनीतिक सुधारों का एजेंडा और इसकी सुधार योजना 25
- प्रशासनिक सुधारों का एजेंडा और इसकी सुधार योजना 30
- आर्थिक सुधारों का एजेंडा और इसकी सुधार योजना 33
- सामाजिक सुधारों का एजेंडा और इसकी सुधार योजना 38
- संस्थागत सुधारों का एजेंडा 41
- विविध सुधार 44
- मोदी सरकार ने परिवर्तन के जिस एजेंडे को लागू किया 45

2. मंत्रालयगत सुधार योजना **47**
- कार्मिक मंत्रालय (पी.एम.ओ.) 47
- रेलवे मंत्रालय 49
- कृषि मंत्रालय 51
- मानव संसाधन मंत्रालय 54
  - शैक्षिक सुधार 54
- ऊर्जा मंत्रालय 56
- वन और पर्यावरण मंत्रालय 57
- खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय 58

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय 61
- श्रम और कल्याण मंत्रालय 63
- विधि और न्याय मंत्रालय 65
  - विधायी मामले 66
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 67
- योजना मंत्रालय 69
- ग्रामीण विकास मंत्रालय 70
  - इंदिरा आवास योजना (प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना) 71
  - सामाजिक सुरक्षा योजना 72
  - भूमि विवाद तथा भूमि रिकॉर्ड 72
  - स्वच्छता अभियान 73
- सार्वजनिक परिवहन मंत्रालय 73
- शहरी विकास मंत्रालय 74
- वित्त मंत्रालय 76
- स्वास्थ्य मंत्रालय 78
- गृह मंत्रालय 81
  - पुलिस सुधार 81
  - राज्य विभाग 83
- केंद्रीय मंत्रालयों का पुनर्गठन 83
- राज्यों के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन 91

भाग-2 (विषयगत खंड)
मौलिक सुधार एजेंडों का विषयपरक खंड

3. भारत की राष्ट्रीय व जातीय स्थिति और इसकी सुधार योजना 95

- एजेंडा हिंदू राष्ट्रवाद का पर आंतरिक सुधार की आहट क्यों नहीं? 96
- रामजन्म भूमि आंदोलन बनाम घर वापसी आंदोलन 102
- चार्ली के बहाने पी.के. और पी.के. के बहाने चार्ली 106
- प्रणब बनाम आरएसएस, सवालों के असल उत्तर तो इतिहासों में छिपे हैं 111
- गांधी को समझने के पहले मोहनदास को समझना जरूरी 116
- कई सवालों के घेरे में है एक राष्ट्र-राज्य के सात दशक का सफर 124
- जनगणना या जातिगणना? 130

- आजादी के आंदोलन में भागीदारी पर मच रही राजनीति 136
- जनता के लिए बनता है मुद्दा, सिर्फ गुड गवर्नेंस का : राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और सामाजिक न्याय, ये सभी मुद्दे नेताओं के लिए 139
- क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रवाद 142
- जरूरत है केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की 146
- या तो अलगाववाद या अलग राज्य 151
- वंचित वर्ग को आरक्षण से नहीं, असल फायदा सशक्तीकरण से 155

4. भारत की राजनीतिक स्थिति और इसकी सुधार योजना 160

- संविधान के प्रति हमारी आत्ममुग्धता कुछ ज्यादा ही है 161
- लोकतंत्र, राजनीति और अर्थव्यवस्था 163
- क्या तय हों सरकारों के प्रदर्शन के मापदंड ? 168
- लोकतंत्र को भावुकता आधारित राजनीति और लुभावने आर्थिक कदमों से मुक्त करने की दरकार 173
- पहले व्यवस्था के व्याकरण तय करिए, फिर अलंकरणों की बात करें 180
- क्यों खतरनाक है लोकतांत्रिक राजनीति में वंशवाद का पनपना 189
- मकसद क्या है इन आंदोलनों व धरनों का ? 197
- क्या हो राजनीतिक दलों की घोषणाओं की बेहतर कसौटी ? 202
  - कसौटी के तत्त्व 206
- क्या है मकसद लोकपाल का, भ्रष्टाचार उन्मूलन या सत्ता हिस्सेदारी ? 209
- सरकारों का जाना और आना, परंतु व्यवस्था का मूल ढाँचा तो वही 215
  - क्या हैं मूल सुधारों के एजेंडे ? 218
- वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ के मायने 221
- संसद् में मची थी सनसनी : हुआ था कैश फार वोट स्कैंडल 226
- आखिर सच सामने आया 227
- मितव्ययिता का ढोंग नहीं, संपत्ति की घोषणा कीजिए : जनता नेताओं की सादगी नहीं, उनके स्विस बैंक के खातों की जाँच चाहती है 231
- भ्रष्टाचार मीडिया के लिए कोई मसाला नहीं, बल्कि व्यवस्था की विरूपता बननी चाहिए 236
- मूल प्रश्न भ्रष्टाचार का 241
- कैसा रहा अब तक का मोदी सरकार का कार्यकाल ? 246

- राजनीतिक आदर्शवाद का अभाव 247
- नीतियों व कार्यक्रमों के मामले में बेहतरीन सरकार 249
- बैंकिंग व वित्तीय मामलों में विफल 251
- मौलिक सुधारों के मामले में यथास्थिति 252
- वादे अमली मामले में लचर 253
- विदेशी मामले में अव्वल 254

5. भारत की आर्थिक स्थिति और इसकी सुधार योजना 256

- महँगाई की आग में जलता रहता देश 257
- पराभव काल भारतीय अर्थव्यवस्था का 262
- हमें जरूरत गरीबी का पैमाना तय करने की नहीं, श्रेणीकरण की है 266
- भ्रष्टाचार और विकास, हैं एक-दूसरे के विलोम 271
- नई आर्थिक नीति का तीसरा दशक : टेलीकॉम आर्थिक सुधारों का रोल मॉडल बनकर उभरा 276
- संकट में कृषि नहीं, किसान : आखिर किसानों का पेट कौन भरेगा 282
- खाद्य सुरक्षा से मिली किसानों की असुरक्षा : देश के गरीबों को चाहिए पोषाहार सुरक्षा और उसके लिए जरूरत है उनकी क्रयशक्ति बढ़ाने की 287
  - वास्तव में आज देश के 80 करोड़ गरीबों को पोषाहार सुरक्षा चाहिए 288
- खेती का संकट : जमीन अधिग्रहण पर हो रही राजनीति और रुक नहीं रहीं किसान आत्महत्याएँ 292
- खेती की तबाही, जरूरत एक मुकम्मल जल प्रबंधन नीति की 300
- मजदूर बहुल राज्यों में ही मजदूरों की कमी 305
- क्या है मनरेगा का सच और ग्रामीण विकास की नई जरूरत? 311
- बाल श्रम किसी सामाजिक कुरीति का नहीं, बल्कि एक आर्थिक मजबूरी का नाम 316
- बैंककर्मियों के साथ ही विसंगति क्यों? 321
- रेल सुधारों की बस औपचारिकता या वास्तविकता भी 324
- भारत में बेरोजगारी का समाधान स्वरोजगार नहीं 327
- सबसे बड़ी लूट तो बैंकों में मची है 335

6. भारत की प्रशासनिक स्थिति और इसकी सुधार योजना 340

- यह ब्यूरोक्रेसी है क्या बला? 341
  - क्या कहते हैं स्वयं नौकरशाह भ्रष्टाचार पर 344

- फैसलों में देरी से 47 हजार करोड़ रुपए का चूना 345
- लोकतांत्रिक भारत के हैं तीन सत्ता केंद्र पी.एम., सी.एम. और डी.एम. 347
- लोकतंत्र के तीनों पहियों का परस्पर असंतुलन 353
- सी.ए.जी. की रिपोर्टों का राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक जवाब चाहिए 359
- नमो सरकार क्या पुरानी नीतियों की प्रतिलिपि? 365
- व्यवस्था की विरूपता, विद्रूपता, विपर्यय और व्यतिक्रम 369
- केरल त्रासदी ने देश में आपदा पूर्व व बाद दोनों की व्यापक तैयारियों के लिए सचेत किया 376

7. भारत की सामाजिक स्थिति और इसकी सुधार योजना 383

- सफाई से दूर स्वच्छता मिशन 384
- भारी चुनौती गंगा-यमुना के प्रदूषण की 389
- क्या आरक्षण ही एक अकेला सामाजिक न्याय है? 396
- युवाशक्ति का महाउद्घोष, क्या हैं इसके मायने 402
  - युवा और महिला एक नैसर्गिक वर्ग, जिसकी कई सामाजिक श्रेणियाँ 403
  - मूल समस्या का निदान 406
- दिल्ली-मुंबई : भारत की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के साथ भारत की सोशियोलॉजी भी 408
- उपभोक्तावाद, भोगवाद, क्या यही है भारत का मध्यवर्गवाद 413

8. भारत की तमाम सार्वजनिक संस्थाओं की स्थिति और इसकी सुधार योजना 417

- न्यायिक सुधारों का एजेंडा 418
  - न्यायिक सुधारों के मुद्दे 422
- जरूरत है पुलिस सुधारों की 425
  - पुलिस सुधार के एजेंडे 429
- देश में स्वतंत्र मीडिया से ज्यादा जरूरत सशक्त, उत्तरदायी व संवैधानिक महत्ता प्राप्त मीडिया की 431
  - क्या हैं मीडिया के मुद्दे? 438
- मास मीडिया मास से वैसे ही दूर है, जैसे कि जनतंत्र जनता से 440
- बदहाल अस्पताल, तंगहाल मरीज, मालामाल डॉक्टर 446
  - मौजूदा डॉक्टरी चैकअप अविश्वसनीय 447

9. आजादी के बाद हमारी आशाओं के आयाम 453

- कौन हैं भारत के सार्वजनिक जीवन के प्रेरणा स्रोत : रोल मॉडल शख्सियतें 454
  - लाल बहादुर शास्त्री 454
  - फील्ड मार्शल मानेक शॉ 455
  - एम.एस. स्वामीनाथन 455
  - वर्गीज कुरियन 456
  - टी.एन. शेषन 456
  - एन. विट्ठल 457
  - सैम पित्रोदा 457
  - राव–मनमोहन–चिदंबरम 458
  - ई. श्रीधरन 459
  - ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 459
  - बाबा रामदेव 460
  - विनोद राय 461
  - प्रणव राय 462
  - बिंदेश्वर पाठक 462
- राज्यों के व्यक्तित्व 463
- संस्थाएँ व संगठन 464
- रोल मॉडल नीतियाँ और निर्णय 465
- नीति नियमन प्राधिकरण : ट्राई, रिजर्व बैंक, सेबी, चुनाव आयोग, सी.ए.जी. 468
- अभियान व कार्यक्रम 470
- वर्तमान की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ 471